दैनिक भारत कि
तामीर
संपादक - काझी मकदूम शफीउद्दीन hinditameer@gmail.com
Editor in chief- Qazi makhdoom shafiuddin

बीड (महाराष्ट्र) | वर्ष-२ ला | अंक-६६ वा | बुधवार १० दिसंबर २०२५ | RNI TITLE CODE:MAHHIN11405/120/1/3/2024 | किमत : २ रूपये | पन्ने - ४

विपक्ष का 'कैश बम' और 'लाडली बहन' पर देवा भाऊ का घर का घेरा!

शीतकालीन अधिवेशन डायरी

- जमीर काझी

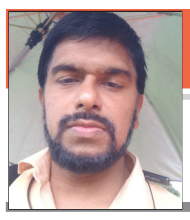

विपक्ष के पास रणक्षेत्र में लड़ने के लिए कोई सेनापति (विपक्ष नेता) नहीं होने से सत्तापक्ष को लग रहा था कि पूरा अधिवेशन एकतरफा हो जाएगा। लेकिन यह उम्मीद दूसरे ही दिन धराशायी हो गई। भारी बहुमत के नशे में महायुती के मंत्री, विधायक और पदाधिकारियों के बेशर्म व्यवहार अब उनके लिए ही मुसीबत बनने लगे हैं। इसका ताजा उदाहरण सामने आया है: अलीबाग के विधायक महेंद्र दलवी का नोटों की गड्डियों वाला कथित वीडियो यानी 'कैश बम', और सत्तापक्ष की ओर से हर बात में 'लाडली बहन' का बार-बार जिक्र आने से स्वयं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस इतने नाराज़ हुए कि उन्होंने अपने ही विधायक को सदन में खुलेआम फटकार लगाई। यह घटना दूसरे दिन चर्चा का विषय बनी रही।

पिछले मानसून सत्र के अंत में शिवसेना (शिंदे गुट) के प्रवक्ता और समाजकल्याण मंत्री संजय शिरसाट का तौलिया लपेटकर नोटों से भरा बैग लिए बैठे फोटो ने खूब बवाल मचाया था। उसी तर्ज पर इस बार पूर्व विपक्ष नेता अंबादास दानवे ने मंगलवार सुबह 'एक्स' पर एक व्यक्ति के हाथ में नोटों की मोटी-मोटी गड्डियाँ लिए हुए फोटो शेयर करते हुए बड़ा 'कैश बम' फोड़ा। बिना किसी विधायक का नाम लिए उन्होंने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से पूछा था - यह 'बंडल बाज' कौन है?

वीडियो में दिख रहे व्यक्ति की कद-काठी और कपड़ों से लग रहा था कि ये अलीबाग के विधायक महेंद्र दलवी ही हैं। दलवी ने तुरंत बयान दिया कि यह मैं नहीं हूँ, -ख से मॉर्फ करके मुझे फँसाया जा रहा है और इसके पीछे महायुती के ही एक घटक दल ने सुपारी दी है। इससे साफ़ ज़ाहिर हो गया कि मुख्यमंत्री और दोनों उपमुख्यमंत्री भले ही बार-बार कहते फिरें कि महायुती में सब कुछ ठीक-ठाक है, लेकिन अंदरूनी कलह बुरी तरह बढ़ रही है। उरण के विधायक महेंद्र थोरवे ने तो सीधे-सीधे सांसद सुनील तटकरे का हाथ बताया, जिससे विवाद और भड़क गया। आने वाले दिनों में रायगढ़ जिले की जिला परिषद और अन्य चुनावों में तटकरे की राष्ट्रवादी और शिंदे की शिवसेना के बीच जंग और तीखी होने वाली है।

इस 'कैश बम' की दिन भर चर्चा होती रही। विधान परिषद में शरद पवार गुट के विधायक शशिकांत शिंदे ने भी मुद्दा उठाया और सत्तापक्ष पर चुनाव में पैसे के दुरुपयोग का जोरदार हमला बोला। उन्होंने माँग की कि यह विधायक कौन है और इतना कैश उसके पास कहाँ से आया, इसकी जाँच हो। भले ही बाकी मामलों की तरह दलवी को भी 'क्लीन चिट' मिल जाए, लेकिन बूंद से गई वो हौद से नहीं आती वाली कहावत के मुताबिक महायुती पर एक और दाग ज़रूर लग गया।

अब आते हैं 'लाडली बहन' वाले मोड़ पर।

विधानसभा चुनाव में महायुती की भारी जीत का एक बड़ा कारण मानी जा रही लाडली बहन योजना की वजह से यह शब्द अब हर बात में घुसाया जाने लगा है, जैसे कोई मुहावरा हो। इससे मुख्यमंत्री पद के तीसरे सीजन में देवा भाऊ बन चुके देवेंद्र फडणवीस इतने खीझ गए हैं कि उन्होंने अपने पूर्व निजी सहायक और भाजपा विधायक अभिमन्यू पवार को सदन में सबके सामने कड़ी फटकार लगाई। बोले - हर बात में लाडली बहन मत लाओ, लाडली बहनों के खिलाफ मत जाओ, वरना घर बैठना पड़ेगा!

अभिमन्यू पवार अपने क्षेत्र में अवैध शराब की समस्या जोर-शोर से उठा रहे थे। उनका कहना था कि लाडली बहनों की सबसे बड़ी समस्या अवैध शराब है, महिलाएँ उनसे इसी की शिकायत करती हैं, इसलिए इस पर सुधार होना चाहिए। विधानसभा अध्यक्ष ने इस बारे में बैठक भी की थी, गृह विभाग और आबकारी विभाग को निर्देश भी दिए गए थे, लेकिन कुछ हुआ नहीं। नतीजा - पवार सहित सभी सत्तापक्ष वालों को मुख्यमंत्री की झाड़ के रूप में जोरदार तमाचा पड़ा। पवार तो आ बैल मुझे मार की हालत में आ गए।

कुल मिलाकर, विपक्ष के 'कैश बम' और खुद के विधायक के 'लाडली बहन' वाले बयान से देवा भाऊ को घर में ही घेर लिया गया!

गुजरात वक्फ ट्रिब्यूनल का बड़ा फैसला - उम्मीद पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के लिए ६ महीने की मोहलत बढ़ी, कोई जुर्माना नहीं!

अहमदाबाद/ हबीब शेख कि रिपोर्ट
९ दिसंबर,

गुजरात स्टेट वक्फ ट्रिब्यूनल ने सोमवार देर शाम एक अहम आदेश जारी करते हुए वक्फ संपत्तियों के अनिवार्य रजिस्ट्रेशन के लिए केंद्र सरकार के उम्मीद (णचएएऊ) पोर्टल पर ६ महीने की अतिरिक्त मोहलत दे दी है। अब गुजरात की सभी वक्फ संपत्तियां ५ जून २०२६ तक बिना किसी जुर्माने के पोर्टल पर रजिस्टर की जा सकेंगी।

ट्रिब्यूनल ने मंजूर की गुजरात वक्फ बोर्ड उएज और एडवोकेट ताहीर हकीम की याचिका

गुजरात वक्फ बोर्ड की मुख्य कार्यकारी अधिकारी (उएज) की ओर से दाखिल याचिका और

जमीयत उलेमा-ए-हिंद (वडोदरा) के वरिष्ठ अधिवक्ता ताहीर हकीम साहब द्वारा सामुदायिक स्तर पर दायर अर्जी

दोनों को ट्रिब्यूनल ने स्वीकार कर लिया।

ट्रिब्यूनल ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि:

नई डेडलाइन: ७ दिसंबर २०२५ से ५ जून २०२६ तक

इस अवधि में रजिस्ट्रेशन पूरी तरह जुर्माना-मुक्त (झशपरश्रीं ऋीशश) रहेगा

पोर्टल की तकनीकी खामियां, झढठ दस्तावेजों में देरी और जमीनी स्तर पर मुतवल्लियों को जागरूकता की कमी को आधार बनाते हुए यह राहत दी गई है

ट्रिब्यूनल ने चेतावनी भी दी है कि यह अंतिम एक्सटेंशन होगा, इसके बाद कोई और मोहलत नहीं दी जाएगी

राज्य में हजारों मस्जिदें-कब्रिस्तान-मदरसे को मिली बड़ी राहत

गुजरात में अभी तक लगभग ४५-५०% वक्फ संपत्तियां ही उम्मीद पोर्टल पर रजिस्टर हो पाई थीं। इस फैसले से:

सैकड़ों मस्जिदें, दरगाहें, कब्रिस्तान, मदरसे और अनाथालय

छोटे-बड़े सभी मुतवल्ली और वक्फ ट्रस्ट

को बड़ी राहत मिली है। अब बिना किसी दबाव और जुर्माने के डेढ़ सौ दिन का अतिरिक्त समय मिल गया है।

अन्य राज्यों से भी अपील - यूपी, बिहार, महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड तुरंत कदम उठाएं

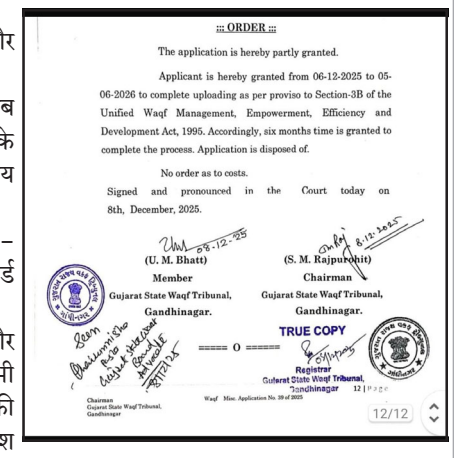

एडवोकेट ताहीर हकीम और जमीयत उलेमा-ए-हिंद ने सभी राज्य वक्फ बोर्डों से अपील की है कि गुजरात और मध्य प्रदेश (भोपाल ट्रिब्यूनल ने भी ६ महीने दिए) की तर्ज पर अपने-अपने राज्य वक्फ ट्रिब्यूनल में तुरंत याचिका दायर करें, ताकि देश की हर वक्फ संपत्ति सरकारी पोर्टल पर सुरक्षित दर्ज हो सके और किसी भी तरह के विवाद या अतिक्रमण से बचाव हो सके।

वक्फ बोर्ड सूत्रों के मुताबिक उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक और महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड भी जल्द ही इसी तरह की याचिकाएं दायर करने की तैयारी कर रहे हैं।

::: ORDER :::

The application is hereby partly granted.

Applicant is hereby granted from 06-12-2025 to 05-06-2026 to complete uploading as per proviso to Section-3B of the Unified Waqf Management, Empowerment, Efficiency and Development Act, 1995. Accordingly, six months time is granted to complete the process. Application is disposed of.

No order as to costs.

Signed and pronounced in the Court today on 8th, December, 2025.

(U. M. Bhatt)
Member
Gujarat State Waqf Tribunal,
Gandhinagar.

(S. M. Rajpurohit)
Chairman
Gujarat State Waqf Tribunal,
Gandhinagar.

===== 0 =====

TRUE COPY
Registrar
Gujarat State Waqf Tribunal,
Gandhinagar

Chairman
Gujarat State Waqf Tribunal,
Gandhinagar

Waqf Misc. Application No. 39 of 2025

12 | Page

12/12

गुटखा पर पूर्ण प्रतिबंध के लिए कानून को और सख्त करेंगे, दोषियों पर लगेगा मकोका : मुख्यमंत्री की गारंटी

जमीर काझी
नागपुर :

महाराष्ट्र में गुटखा विक्रेताओं पर मकोका (चउजउ-) लगाने के लिए कानून में संशोधन करने जा रहा है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विधानसभा में घोषणा की कि गुटखा कारोबारियों पर मकोका लागू करने का प्रस्ताव विधि एवं न्याय विभाग को भेजा गया था, लेकिन वर्तमान कानून में 'हानि और चोट' (क्रीा र्कीीं) दोनों तत्वों की अनुपस्थिति के कारण इसे लागू नहीं किया जा सकता। इसलिए अब कानून में जरूरी संशोधन कर इसे और सख्त बनाया जाएगा, ताकि गुटखा बेचने वालों पर भी मकोका का शिकंजा कसा जा सके।

विधानसभा सदस्य प्रशांत ठाकुर, असलम शेख, अभिमन्यू पवार, रईस शेख और अमीन पटेल ने स्कूल-कॉलेज परिसर में अवैध गुटखा बिक्री और परिवहन के मुद्दे पर सवाल उठाया था। उसके जवाब में मुख्यमंत्री फडणवीस बोल रहे थे।

उन्होंने बताया कि राज्य में गुटखा पूरी तरह प्रतिबंधित है। पुलिस ने पूरे राज्य में बड़ी कार्रवाई की है और सैकड़ों मुकदमे दर्ज किए गए हैं। प्रमुख आंकड़े इस प्रकार हैं:

नवी मुंबई में १,१४४
अहमदनगर में १८५
जालना में ९०
अकोला में ३५
नासिक में १३१
चंद्रपुर में २३०
सोलापुर में १०८
बुलढाणा में ६६४
नागपुर एवं यवतमाळ में १,७०६ मुकदमे दर्ज

मुख्यमंत्री ने कहा कि अब स्कूल-कॉलेज के १०० मीटर दायरे में अगर गुटखा बिक्री पकड़ी गई तो वहाँ की टपरियाँ और दुकानें सील करने के लिए पुलिस को सख्त निर्देश दिए गए हैं। यह कार्रवाई स्थानीय निकायों के साथ मिलकर की जाएगी।

साथ ही, नशे की लत में फँसे लोगों के लिए अच्छे पुनर्वास केंद्रों की जरूरत पर जोर जोर देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि मुंबई महानगर क्षेत्र में क्वालिटी रिहैब सेंटरों की भारी कमी है। सरकार इस दिशा में तुरंत पहल करेगी और नए केंद्र खोलेगी।

लिंबागणेश क्षेत्र में तेंदुओं की बढ़ती गतिविधि; किसान भयभीत

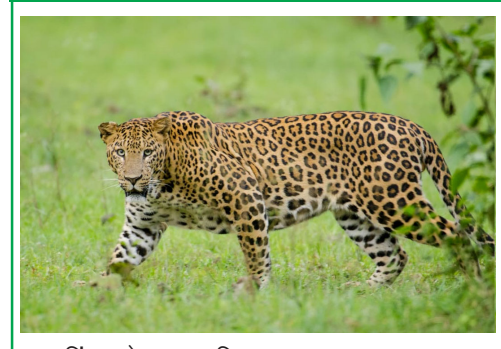

कृषि पंपों के लिए दिन में बिजली आपूर्ति की मांग - गुरुवार को रास्ता रोको आंदोलन की चेतावनी :- डॉ. गणेश ढवळे

लिंबागणेश :- (दि. ०९)

बीड तालुका के लिंबागणेश क्षेत्र में तेंदुए दिखाई देने से ग्रामीण और किसान भयभीत हो गए हैं। रात के समय कृषि पंपों की बिजली आपूर्ति चालू रहने के कारण किसानों को अंधेरे में खेत पर जाना पड़ता है, जिससे उनके जीवन को गंभीर खतरा पैदा हो गया है।

इस पृष्ठभूमि में कृषि पंपों के लिए रात की बजाय दिन में नियमित बिजली आपूर्ति शुरू करने की मुख्य मांग को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता तथा मुख्य प्रचार प्रमुख, बीड जिला सूचना अधिकार कार्यकर्ता महासंघ महाराष्ट्र राज्य के जिला अध्यक्ष डॉ. गणेश ढवळे लिंबागणेशकर के नेतृत्व में आगामी ११ दिसंबर, गुरुवार को लिंबागणेश बस स्टैंड पर रास्ता रोको आंदोलन किया जाएगा। इसकी लिखित नोटिस जिला कलेक्टर, कार्यकारी अभियंता महावितरण बीड तथा सहायक अभियंता उपकेंद्र लिंबागणेश को दी गई है।

पोखरी और पिंपरनई क्षेत्र के किसानों ने तेंदुओं के बढ़ते वावर की जानकारी दी है, जिससे भय का माहौल और गहरा गया है। जिले में पहले भी तेंदुए के हमले में किसान और ग्रामीणों की मौत हो चुकी है, इसलिए इस स्थिति की अनदेखी खतरनाक साबित हो सकती है।

लिंबागणेश, पिंपरनई, पोखरी, बेलगाव, सोमनाथवाडी, मसेवाडी, मोरगाव, फुकेवाडी, काळेवाडी और गणेशनगर इन क्षेत्रों में रात की बिजली आपूर्ति बंद कर दिन में नियमित और पर्याप्त बिजली देने की मांग किसानों व ग्रामीणों ने निवेदन के माध्यम से की है।

संसदीय अभ्यासवर्ग के माध्यम से लोकतंत्र की प्रक्रिया को समझने का अवसर-मुख्यमंत्री

विधानमंडल में ५१वें संसदीय अभ्यासवर्ग का उद्घाटन

तभा वृत्तसेवा/विशेष प्रतिनिधि

नागपुर, दि. ९ दिसंबर : भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर द्वारा निर्मित संविधान में नागरिकों की आशाओं, आकांक्षाओं और अपेक्षाओं को पूरा करने की पूरी व्यवस्था है। अनेक चुनौतियों का सामना करते हुए हमारी लोकतंत्र और संवैधानिक संस्थाएँ परिपक्व हुई हैं तथा संविधान ने लोकतंत्र की अत्यंत सुंदर संरचना की है। संसदीय अभ्यासवर्ग के जरिए लोकतंत्र की प्रक्रिया को निकट से समझने का अवसर मिलता है - यह विचार मंगलवार को मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने व्यक्त किया।

वे विधानभवन में ५१वें संसदीय अभ्यासवर्ग के मुख्यमंत्री के हाथों उद्घाटन समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर विधान परिषद सभापति प्रो. राम शिंदे, विधानसभा अध्यक्ष एड. राहुल नार्वेकर, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, विधान परिषद उपसभापति डॉ. नीलम गोरे, विधानसभा उपाध्यक्ष अण्णा बनसोडे, संसदीय कार्यमंत्री चंद्रकांत पाटील, सांस्कृतिक कार्यमंत्री तथा कॉमनवेल्थ संसदीय संघ के कोषाध्यक्ष एड. आशीष शेलार आदि उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि संसदीय अभ्यासवर्ग लोकतंत्र से परिचय कराने वाला वर्ग है। पुस्तकी पाठ्यक्रमों में हम लोकतंत्र के मूल्य और प्रक्रिया पढ़ते हैं, लेकिन इस अभ्यासवर्ग में उसे प्रत्यक्ष देखने का मौका मिलता है। राज्य का शासन कैसे चलना चाहिए, इसके नियम संविधान ने दिए हैं। विधानसभा और विधान परिषद दोनों सदनों के नियम, उनमें प्रयुक्त हर शब्द और प्रावधान संविधान पर ही आधारित हैं। विधानमंडल के कामकाज की सुंदर संरचना संविधान ने दी है।

उन्होंने आगे कहा -

विधानमंडल में जनता की आशा-आकांक्षाओं को पूरा करने वाले लोग बैठते हैं। जब कोई कानून बनता है तो सदन में होने वाली चर्चा गुणवत्तापूर्ण होती है। राज्य के आखिरी व्यक्ति पर उस कानून का क्या असर होगा, यह पक्ष भी सदन में रखा जाता है। विधानमंडल की मंजूरी के बिना राज्य के खजाने से एक रुपया भी खर्च नहीं हो सकता। विभागों को अपनी मांगें सदन के सामने रखनी पड़ती हैं, उन पर चर्चा होती है, स्वीकृति के बाद बजट बनता है और फिर कानून बनाना पड़ता है। यही कानून राज्य के खजाने की चाबी है।

राज्य की छोटी-सी घटना के भी विधानमंडल में प्रतिध्वनि सुनाई देती है। लोकतंत्र की प्रक्रिया विधानमंडल के काम से ही जीवंत रहती है। सदन के सभापति और अध्यक्ष हमारे हेडमास्टर हैं; उनकी अनुमति के बिना सदन में कुछ भी नहीं हो सकता। संसदीय लोकतंत्र में कई तरह के हथियार हैं; ये हथियार लोकतंत्र को मजबूत करने के महत्वपूर्ण साधन हैं।

सभापति प्रो. राम शिंदे ने कहा -

भारतीय गणतंत्र के ७५ वर्ष पूरे होने के समय ५१वां संसदीय अभ्यासवर्ग शुरू हो रहा है। हमारे देश में संसदीय लोकतंत्र को अनुपम महत्व है। विधानमंडल के माध्यम से लोकतंत्र का प्रतिबिंब दिखाई देता है और आम नागरिकों तक योजनाएँ तथा राज्य को प्रगति की दिशा मिलती है।

विधानसभा अध्यक्ष एड. राहुल नार्वेकर ने कहा -

कॉमनवेल्थ संसदीय संघ का यह अभ्यासवर्ग सबसे पुराना और महत्वपूर्ण है तथा संसदीय लोकतंत्र को मजबूत करने का एक बड़ा उपक्रम है। यदि संसदीय लोकतंत्र को और सशक्त करना है तो इसकी जानकारी जन-जन तक पहुँचनी चाहिए।

उर्दू दैनिक तामीर के २५ वो साल में क़दम रखने पर एक और पेशकश

मुंबई में खतरनाक वायु प्रदूषण, सांस की बीमारियों में तेज इजाफा, तत्काल कार्रवाई की मांग

कांग्रेस अध्यक्ष एवं सांसद वर्षा गायकवाड़ ने लोकसभा में मुंबई की बिगड़ती हवा की गुणवत्ता का मुद्दा जोरदार तरीके से उठाया

मुंबई संवाददाता

मुंबई: देश की आर्थिक राजधानी और विश्व प्रसिद्ध शहर मुंबई को वायु प्रदूषण के गंभीर संकट ने स्वास्थ्य के लिए बड़े खतरे में धकेल दिया है। शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स (-टख) लगातार १५० से २०० के बीच बना हुआ है, जिससे सांस संबंधी बीमारियों में तेजी से वृद्धि हो रही है। कई इलाकों में तो -टख ३०० के पार पहुंच गया है, जो अत्यंत स्वास्थ्य-विरोधी है।

मुंबई कांग्रेस की अध्यक्ष एवं सांसद वर्षा गायकवाड़ ने लोकसभा में इस गंभीर स्थिति पर गहरी चिंता जताते हुए कहा कि मुंबईवासियों को साफ और सुरक्षित हवा देना सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी है। इसके लिए निर्माण कार्यों पर तत्काल रोक, एंटी-स्मॉग गन, निर्माण स्थलों पर व्हील वॉश सिस्टम और अन्य आपात उपाय अनिवार्य हैं।

रूल ३७७ के तहत मुद्दा उठाते हुए वर्षा गायकवाड़ ने कहा कि पूरे मुंबई में -टख लगातार खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है। बेतहाशा निर्माण कार्य, पेड़ों की अवैज्ञानिक कटाई और पर्यावरण को नजरअंदाज करने वाली सरकारी नीतियों ने राज्य के पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंचाया है। उन्होंने बताया कि देश में हर साल लगभग १७ लाख लोग वायु प्रदूषण के कारण असमय मौत का शिकार हो जाते हैं, जबकि एक वैज्ञानिक अध्ययन के अनुसार मुंबईकरों की औसत आयु ३.७ साल कम हो चुकी है।

उन्होंने आरे कॉलोनी में मेट्रो कार शेड के लिए २,००० से अधिक पेड़ों की कटाई, धारावी पुनर्विकास के दौरान बड़े पैमाने पर पेड़ों का सफाया और नासिक में साधोग्राम के लिए प्रस्तावित १,७०० पेड़ों की कटाई का जिक्र करते हुए कहा कि इन सबने पर्यावरण संतुलन को गंभीर रूप से बिगाड़ दिया है, जिससे हवा में जहरीले कणों की मात्रा खतरनाक स्तर तक बढ़ गई है।

वर्षा गायकवाड़ ने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने उनके 'मुंबई क्लीन एयर मेनिफेस्टो' में दिए गए सुझावों के अनुसार तत्काल और सख्त कदम नहीं उठाए तो मुंबई की हालत दिल्ली से भी बदतर हो सकती है। उन्होंने जोर देकर कहा कि नागरिकों के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए पर्यावरण-अनुकूल विकास रणनीति और पेड़ों के संरक्षण को सर्वोच्च प्राथमिकता देना आज की सबसे बड़ी जरूरत है।

राज्यस्तरीय वीर शिवछत्रपती महाराष्ट्र रत्न पुरस्कार से हैप्पी टू हेल्प फाउंडेशन के संस्थापक अध्यक्ष शेख अब्दुल रहीम सम्मानित!

शेख अब्दुल रहीम ने यह पुरस्कार अपनी स्वर्गीय मातोश्री आबेदाबी को समर्पित किया

छत्रपती संभाजीनगर : हैप्पी टू हेल्प फाउंडेशन के संस्थापक अध्यक्ष शेख अब्दुल रहीम रहीम को अनाथ सेवक सामाजिक कल्याण संस्था, अहमदनगर की ओर से प्रदान किया जाने वाला राज्यस्तरीय वीर शिवछत्रपती महाराष्ट्र रत्न पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया है। शिक्षा और सामाजिक क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय कार्य को देखते हुए यह सम्मान घोषित किया गया था। किसी कारणवश शेख अब्दुल रहीम अहमदनगर में आयोजित कार्यक्रम में उपस्थित नहीं हो सके, इसलिए अनाथ सेवक सामाजिक कल्याण संस्था, अहमदनगर के संस्थापक अध्यक्ष श्री तुषार अर्जुन बोरुडे ने यह पुरस्कार छत्रपती संभाजीनगर में समाजसेविका श्रीमती मीरा ताई के हाथों सुपुर्द करवाया।

शेख अब्दुल रहीम सर ने अल्पसंख्याक समाज के छात्रों और शिक्षकों की प्रगति के लिए हैप्पी टू हेल्प फाउंडेशन के माध्यम से अनेक महत्वपूर्ण कार्यक्रम चलाए हैं। शैक्षणिक सामग्री वितरण, करियर मार्गदर्शन, विभिन्न प्रतियोगिताएं, रक्तदान शिविर, पर्यावरण संरक्षण अभियान, महिला सशक्तीकरण कार्यक्रम तथा छात्र-शिक्षकों की समस्याओं के लिए गली से दिल्ली तक लगातार संघर्ष करते रहे हैं। इन विविध कार्यक्रमों के कारण समाज में उनकी एक आदर्श और कार्यनिष्ठ छवि बनी है।

उनके कार्य की सराहना करते हुए अब तक उन्हें जिला, संभाग, राज्य और राष्ट्रीय स्तर के कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों से नवाजा जा चुका है। शिक्षा एवं समाजसेवा के क्षेत्र में उनका योगदान उल्लेखनीय है और वीर शिवछत्रपती महाराष्ट्र रत्न यह सम्मान उनके कार्य को नई ऊर्जा और प्रेरणा देने वाला साबित हुआ है। उन्होंने यह पुरस्कार अपनी स्वर्गीय मातोश्री आबेदाबी को समर्पित किया है।

अधिवेशन के दूसरे दिन किसानों के मुद्दे पर विपक्ष का विधानमंडल की सीढ़ियों पर आंदोलन

विशेष प्रतिनिधि

नागपुर :

राज्य में हर दिन ८ किसान आत्महत्या कर रहे हैं, लेकिन महायुती सरकार किसानों के लिए केवल घोषणाएँ करती है, जबकि हकीकत में सरकार के सारे नीतियाँ किसान-विरोधी रही हैं। इस तीखी आलोचना के साथ महाविकास आघाड़ी ने विधानमंडल के दूसरे दिन विधान भवन की सीढ़ियों पर जोरदार आंदोलन किया।

विपक्षी सदस्यों ने सरकार-विरोधी नारे लगाते हुए पूरे परिसर को गूँजने नहीं दिया।

महायुती सरकार ने किसानों को कर्जमाफी का वादा किया था, लेकिन आज तक कर्जमाफी नहीं की गई।

कपास को समर्थन मूल्य नहीं मिल रहा है।

कपास पर आयात शुल्क शून्य कर दिया गया है, जिससे विदेशी कपास भारत में सस्ते में आ रहा है।

सोयाबीन खरीदी केंद्र अभी तक शुरू नहीं हुए हैं और धान को भी बोनस नहीं मिल रहा है।

इन सभी मुद्दों के खिलाफ विपक्ष ने सीढ़ियों पर धरना-प्रदर्शन किया। धोखेबाज सरकार, किसानों का कर्ज माफ होना चाहिए, कपास और सोयाबीन को उचित भाव मिलना चाहिए जैसी जोरदार नारेबाजी विपक्षी सदस्यों ने की।

जिला परिषद उर्दू हाईस्कूल व जूनियर कॉलेज, गेवराई में भव्य पुरस्कार वितरण समारोह

मेधावी छात्राओं को गोल्ड मेडल, प्रशस्ति-पत्र और पुष्पगुच्छ देकर सम्मानित किया गया

गेवराई (बीड), ०८ दिसंबर २०२५: जिला परिषद उर्दू हाईस्कूल एवं जूनियर कॉलेज, गेवराई में सोमवार को एक भव्य पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में सुलेखन (उर्दू, अंग्रेजी, मराठी), सीरतुन नबी ﷺ, नात, वक्तृत्व और लेखन स्पर्धाओं में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त करने वाली छात्राओं का सम्मान किया गया।

समारोह की अध्यक्षता शाइस्ता बाजी ने की, जबकि मुख्य अतिथि के रूप में मौलवी फारुकी रब्बानी सर उपस्थित थे। अन्य माननीय अतिथियों में फरहीन बाजी, रुही कहकशाँ बाजी, सुमैया सौदागर बाजी और अरम ज़रीन बाजी शामिल थीं।

कार्यक्रम की शुरुआत कुरआन पठन और नात पठन से हुई। इसके बाद अध्यक्ष, मुख्य अतिथि तथा अन्य उपस्थित माननीय शिक्षकों के हाथों मेधावी छात्राओं को गोल्ड मेडल, प्रशस्ति-पत्र और पुष्पगुच्छ प्रदान किए गए।

पुरस्कार प्राप्त छात्राओं ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि स्पर्धा की प्रशासनिक तैयारी सराहनीय रही तथा भविष्य में भी ऐसी स्पर्धाओं में उत्साहपूर्वक भाग लेने का संकल्प लिया। साथ ही उन्होंने अधिक से अधिक शैक्षणिक एवं नैतिक स्पर्धाओं के आयोजन की इच्छा भी जताई।

प्रसिद्ध शिक्षक मुहम्मद इलियास सर ने अपने प्रेरणादायी भाषण में पैगंबर मुहम्मद ﷺ की सीरत का महत्व बताया और कहा कि उनकी शिक्षाओं का अनुसरण ही आज के युग में शांतिपूर्ण एवं आदर्श समाज की रचना का एकमात्र साधन है।

समारोह की अध्यक्ष शाइस्ता बाजी ने अपने अध्यक्षीय भाषण में मेधावी छात्राओं को बधाई दी तथा उच्च शैक्षणिक लक्ष्य प्राप्त करने और विभिन्न स्पर्धाओं में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए मुहम्मद इलियास सर के योगदान की विशेष प्रशंसा की।

कार्यक्रम का संचालन दसवीं कक्षा की मेधावी छात्राओं हरबट अरूबा और सय्यदा हबीबा ने अत्यंत कुशलता से किया। अंत में शेख ताहूरा फिरोज ने आभार प्रदर्शन किया और दुआ के साथ यह भव्य समारोह संपन्न हुआ।

शौचालय इस्तेमाल के लायक नहीं होने से बच्चों को घर जाना पड़ता है!

कोंबडं बस्ती ज़िला परिषद स्कूल का चौंकाने वाला मामला, कागज़ों पर ही अभियान चलाने के लिए सीईओ को ही अवॉर्ड दे दो! - डॉ. गणेश ढवळे

लिंबागणेश (९ दिसंबर)

केंद्र और राज्य सरकार के निर्देशानुसार 'विश्व शौचालय दिवस' (१९ नवंबर) से 'मानव अधिकार दिवस' (१० दिसंबर) तक पूरे ज़िले में हमारा शौचालय - हमारा अभिमान नामक विशेष अभियान चलाने के आदेश ज़िला परिषद प्रशासन ने जारी किए थे। ज़िले के १,३५६ गाँवों में निजी और सार्वजनिक शौचालयों की मरम्मत, पुताई और नियमित उपयोग सुनिश्चित करने की अपील मुख्य कार्यकारी अधिकारी जीतिन रहमान ने की थी। उन्होंने यह भी कहा था कि शौचालय केवल सुविधा नहीं, बल्कि स्वास्थ्य, सुरक्षा और सम्मान की गारंटी है।

लेकिन ज़मीनी हकीकत क्या है?

एक बार फिर साबित हो गया कि अभियान सिर्फ़ कागज़ों तक ही सीमित रहा।

कोंबडं बस्ती स्कूल के शौचालय कई सालों से बंद!

बच्चों की बदहाली

बीड तालुका के महाजनवाडी स्थित लिंबागणेश केंद्र के अंतर्गत आने वाले कोंबडं बस्ती ज़िला परिषद स्कूल के शौचालय कई वर्षों से बंद और पूरी तरह खराब पड़े हैं। नतीजतन, बच्चों को शौच के लिए शिक्षक से इजाज़त लेकर घर जाना पड़ता है। यह दर्द बच्चों ने सामाजिक कार्यकर्ता डॉ. गणेश ढवळे (लिंबागणेश) से बातचीत में व्यक्त किया।

अभियान का आखिरी दिन यानी १० दिसंबर को 'उत्तम शौचालय पुरस्कार' देने की घोषणा प्रशासन कर रहा है, लेकिन जो शौचालय हैं ही नहीं, उनकी चमचमाती कागजी रिपोर्ट बिल्कुल तैयार है।

इस पर तंज कसते हुए डॉ. ढवळे ने कहा, कागज़ों पर शानदार अभियान चलाने के लिए सबसे बड़ा अवॉर्ड तो उएज जीतिन रहमान के गले में ही डाल दो!

स्थानीय प्रतिनिधियों को भी जानकारी नहीं!

महाजनवाडी के सरपंच विश्वंभर गिरी और स्कूल के शिक्षक रोहन मुंडे से जब इस विशेष अभियान के बारे में पूछा गया तो उन्होंने साफ़ कहा,

हमें प्रशासन की तरफ़ से अभियान शुरू होने की कोई सूचना या पत्र तक नहीं मिला।

बच्चों का असली दर्द

सई रामचंद्र घरत - कक्षा ४

स्कूल का शौचालय तो इस्तेमाल में है ही नहीं, इसलिए सर से कहकर घर जाना पड़ता है।

चैतन्य चांगदेव घरत - छात्र

मेरा घर दूर है, इसलिए मैं दोस्त विराज घरत के घर जाता हूँ।

इतनी बुनियादी सुविधा के लिए भी बच्चों को इधर-उधर भटकना पड़ रहा है, यह बेहद चिंताजनक और शर्मनाक स्थिति है।

बीड नगर परिषद में रिश्वत लेते क्लर्क एसीबी के जाल में फंसा

मंगलवार, ९ दिसंबर २०२५

बीड: गुंठेवारी की सत्यप्रत (प्रमाण पत्र) देने के एवज में १,००० रुपये की रिश्वत लेते हुए बीड नगर परिषद के अभिलेख विभाग के कर्मचारी आशिष मस्के को मंगलवार (९ दिसंबर) को बीड के लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग (एसीबी) की टीम ने रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया।

जिले में रिश्वतखोरी की घटनाएँ लगातार बढ़ रही हैं। ताजा मामला बीड नगर परिषद का है, जहाँ एक नागरिक से गुंठेवारी का प्रमाण पत्र देने के बदले आशिष मस्के ने एक हजार रुपये की रिश्वत मांगी थी। शिकायत मिलते ही एसीबी ने जाल बिछाया और मस्के को रिश्वत की रकम लेते दबोच लिया। इस मामले में बीड शहर पुलिस स्टेशन में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत अपराध दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। कार्रवाई लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग के उपअधीक्षक सोपान चिट्टमपल्ली के मार्गदर्शन में हुई। इस गिरफ्तारी से बीड नगर परिषद में हड़कंप मच गया है।

'बीजेपी चुनाव आयोग को वोट चोरी करने का औजार बना रही है'-राहुल गांधी

दिल्ली। वृत्तसंस्था

राहुल गांधी लगातार बीजेपी और चुनाव आयोग पर 'वोट चोरी का आरोप लगा रही है। बुधवार को उन्होंने एक बार फिर बीजेपी और चुनाव आयोग पर यह आरोप लगाया। राहुल गांधी ने द पर पोस्ट कर कहा कि जनता बीजेपी से तीन सवाल पूछ रही है।

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा, भारत की जनता ये ३ बहुत जरूरी और सीधे सवाल पूछ रही है: १. उगख को एउ चयन पैनल से क्यों

हटाया?, २. २०२४ चुनाव से पहले एउ को लगभग पूरी कानूनी इम्युनिटी क्यों दी?, ३. उउढत फुटेज ४५ दिन में नष्ट करने की इतनी जल्दबाज़ी क्यों?

राहुल गांधी ने मंगलवार को आरोप लगाया था कि बीजेपी 'वोट चोरी' के जरिए 'आइडिया ऑफ इंडिया' नष्ट कर रही है। उन्होंने लोकसभा में चुनाव सुधारों पर चर्चा के दौरान २०२३ के निर्वाचन कानून का उल्लेख करते हुए चेतावनी भरे लहजे में कहा था कि कांग्रेस की सरकार बनने पर इस कानून में पूर्वव्यापी प्रभाव से संशोधन किया जाएगा तथा चुनाव आयुक्तों को कठघरे में लिया जाएगा।

दैनिक भारत की तामीर अखबार के मालिक, मुद्रक, प्रकाशक, संपादक काजी मखदूम शफीउद्दीन ने आरएम प्रिंटरर्स, बार्शी रोड, बीड 431122 महाराष्ट्र में मुद्रित कर के दैनिक तामीर, नगर परिषद परिसर, बशीर गंज, बीड, महाराष्ट्र कार्यालय से प्रकाशित किया है। मोबाइल : 9270574444 ईमेल : hinditameer@gmail.com वेबसाइट : www.dailytameer.com

daily Bharat ki tameer newspaper owner printer publisher editor Quazi makhdoom shafiuddin has printed at RM printers barshi road beed 431122 Maharashtra at published at office daily tameer nagar parishad complex Bashir gunj beed Maharashtra. Mobile : 9270574444 Email : hinditameer@gmail.com Website : www.dailytameer.com